जल शक्ति अभियान से होगा जल संकट का समाधान

चन्दन कुमार चौधरी

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत ने जल संरक्षण के उद्देश्य से 'संचय जल, बेहतर कल थीम' से एक जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान की शुरुआत की. केन्द्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य देश में हर साल गंभीर होते जल संकट का स्थायी समाधान करने के वास्ते मिशन मोड पर काम करने के लिए रणनीति तैयार करना है. इसके लिए केन्द्र सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत अतिरिक्त और संयुक्त सचिवों सहित 255 वरिष्ठ अधिकारियों को देश में पानी के कमी वाले जिलों का प्रभारी बनाया है जिससे इन इलाकों में जल संरक्षण की योजना बनाई जा सके. इस योजना का लक्ष्य जल संरक्षण और सिंचाई कुशलता को जल आंदोलन बनाना है. इसके लिए सरकार ने 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 255 जिलों की पहचान की है. साथ ही पानी की कमी वाले 1593 ब्लॉकों की भी पहचान की गई है इनमें से 313 ब्लॉक में पानी का गंभीर संकट है.

दरअसल केन्द्र सरकार देश में जल संकट और पानी से जुड़ी समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जिसे जल शक्ति मंत्रालय नाम दिया गया है.

इस योजना के तहत क्या होगा?

इस योजना के तहत सरकार के अतिरिक्त और संयुक्त सचिव स्तर सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 255 जिलों में जाएंगे और इस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे. केन्द्र सरकार की तीन-चार ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत राज्य सरकारों को जल संरक्षण के लिए धन मुहैया कराया जाता है. ये अधिकारी उन योजनाओं की जमीनी हकीकतों की पड़ताल करेंगे और उसमें समन्वय का काम करेंगे. साथ ही साथ ये अधिकारी वहां के लोगों को जल संरक्षण को आंदोलन में कैसे बदला जाए, यह समझाने का प्रयास करेंगे और इस दिशा में काम करेंगे. साथ ही इन अधिकारियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित जल संरक्षण के लिए निर्धारित पांच विषयों पर काम सौंपा जाएगा. इनमें वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, सघन वनीकरण और पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों के नवनीकरण के साथ-साथ वाटरशेड विकास शामिल है.

मन की बात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में मन की बात के पहले ही कार्यक्रम में पानी से जुड़ी चुनौती का जिक्र किया था. इससे पता लगता है कि पानी की समस्या के समाधान को लेकर वे कितने गंभीर हैं. उन्होंने कहा था कि पानी का हमारी संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्व है. पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने को लेकर उन्होंने कहा था कि जन भागीदारी, जन शक्ति, 130 करोड़ देश वासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लिया जाएगा. पीएम ने कहा कि देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है जिससे पानी से जुड़े विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे. उन्होंने पानी के संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी और सहयोग पर बल दिया था.

प्रधानमंत्री की अपील

प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और इससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए देशवासियों से तीन अनुरोध भी किए थे. उन्होंने देशवासियों से कहा कि स्वच्छता की तरह ही जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाए और इसमें जन भागीदारी बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई तौर-तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं. ऐसे में आप सभी लोग जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को साझा करें. तीसरे अनुरोध में प्रधानमंत्री ने हैशटैगजलशक्ति4जलशक्ति का उपयोग कर जानकारी साझा करने की अपील की थी जिससे जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी की जानकारी का एक डेटाबेस बनाया जा सके. बाद में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट भी किया जिसे हजारों लोगों ने रिट्वीट किया था.

नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नै और हैदराबाद सहित 21 भारतीय शहरों में 2020 तक भूजल खत्म हो जाएगा. साथ ही दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नै और हैदराबाद के लोगों को सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ेगा. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से ही पानी की परेशानी शुरू हो जाएगी. पानी के कारण करीब 10 करोड़ लोग दिक्कत का सामना करेंगे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत के 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा. नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित है. निश्चित रूप से नीति आयोग की यह रिपोर्ट चिंतित करने वाली है. हमने जिस तरह से पानी प्रदूषित किया है और उसमें बेतहाशा कचरा डाला है, उससे आज हमारे देश में 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हो गया है. तभी तो जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत दुनिया की 122 देशों की सूची में 120 वें स्थान पर है. जल सूचकांक रैंकिंग के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है तो मध्यप्रदेश दूसरे जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है. बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हैं. प्रदूषित पानी के कारण हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सरकार का मानना है कि देश में हर साल प्रदूषित पानी से दो लाख लोग मर जाते हैं और हर दिन 500 से अधिक मौतें होती हैं. हमें ध्यान रखना होगा कि ये व्यक्ति स्वच्छ पानी के अभाव में मारे जा रहे हैं. थोड़ी सतर्कता और दृढ़ इच्छाशक्ति से स्वच्छ पानी मुहैया कराना मुश्किल काम नहीं है. हमें समझना होगा कि स्वच्छ पानी के अभाव में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इसके इलाज में भी लोगों को काफी रुपया खर्च करना पड़ता है. जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कई राज्य ऐसे हैं जहां साफ पानी यानी पीने का पानी पांच प्रतिशत से भी कम मात्रा में उपलब्ध है.

वर्षा जल संचयन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि साल भर में वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उसका केवल आठ प्रतिशत ही हमारे देश में बचाया जाता है और अब सरकार की योजना इसे बढ़ा कर जल संकट से निपटने की है. ऐसे में निश्चित रूप से हमें वर्षा जल संचयन बढ़ाने की जरूरत है. जल शक्ति मंत्री का कहना है कि देश में बारिश और अन्य संसाधनों से मिलने वाले जल का केवल पांच प्रतिशत ही पेयजल में इस्तेमाल हो पाता है. हमें समझना होगा कि समय के साथ हमारे यहां प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में कमी आई है. 2011 में जहां प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जहां 1,816 क्यूबिक मीटर थी वहीं 2011 में यह 1,545 क्यूबिक मीटर हो गई. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अनुमान के मुताबिक 2025 तक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1,345 क्यूबिक मीटर हो जाएगी.

राजस्थान ने कर दिखाया

इसके अलावा हमें जल संरक्षण की पुरानी तकनीक और वर्षा जल संरक्षण पर भी समुचित तरीके से ध्यान देना ही होगा. राजस्थान राज्य ने पिछले 70 में से 60 साल सूखा देखा है लेकिन उसने जल संरक्षण से बहुत कुछ मुमकिन करके दिखाया है. यहां पर बारिश के मौसम में छत पर पानी जमा किया जाता था जिसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और यह साल भर काम आता था. भारत में दुनिया की करीब 18 प्रतिशत आबादी रहती है और हमारे ज्यादातर जलस्रोत प्रदूषित हो गए हैं. हमारे यहां पानी और खेती की 65 प्रतिशत जरूरतें भू-जल से पूरी होती हैं और हम हैं कि इसका बेतहाशा दोहन करते जा रहे हैं. देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब टैंकर और डिब्बाबंद पानी पर निर्भर होता जा रहा है. हालांकि, हमें समझना होगा कि 20 लीटर वाले पानी के डिब्बे को भरने के लिए हमें 40 लीटर भूजल का इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे और जल संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं होंगे तो हमारे सामने पानी का संकट विकराल होगा ही और हम डिसैलिनेशन जैसे संयंत्रों पर निर्भर होते चले जाएंगे. हमारे सामने इजराइल का उदाहरण है जिसने जल संकट को एक अवसर के रूप में बदल दिया. वहां भारत की तुलना में एक चौथाई बारिश होती है लेकिन पानी के मामले में वे सुरक्षित हैं.

डिसैलिनेशन संयंत्र

देश में जारी भारी जल संकट के बीच नीति आयोग ने देश की करीब 7800 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के पास तैरते हुए या तट पर बड़े डिसैलिनेशन संयंत्र लगाने का सुझाव दिया है. सरकार चाहती है कि जिन इलाकों में भूजल स्तर काफी कम हो गया है, वहां डिसैलिनेशन से पानी मुहैया कराया जाए. इसके लिए नीति आयोग जल्द ही उन तकनीकों की जानकारी पेश करेगा जिसका इस्तेमाल विभिन्न राज्य डिसैलिनेशन संयंत्र लगाने के लिए कर सकते हैं. डिसैलिनेशन संयंत्र एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए समुद्री खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है।

प्रधानमंत्री ने सरपंचों को लिखा था पत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2019 में मानसून के मौसम से पहले देश भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरपंचों को पत्र लिखे थे और उनसे ग्रामीण भारत में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की गतिविधियां शुरू करने का अनुरोध किया था. इन गतिविधियों में वर्षा जल भंडारण के लिए छोटे तालाबों का निर्माण और सफाई करना, वृक्षारोपण अभियान, वर्षा जल के संचयन के लिए भंडारण टैंक का निर्माण और वनीकरण शामिल था. प्रधानमंत्री द्वारा 2.3 लाख से अधिक सरपंचों को लिखे पत्र के प्रभाव का उल्लेख करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा था कि यह लोगों को वर्षा जल संचयन, तालाबों और गांवों की टंकियों के रख-रखाव और पानी के संरक्षण में मदद करेगा.

अटल भू-जल योजना

पानी से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कितने गंभीर हैं वह इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पानी बचाने का मंत्र देते हुए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने देश के सभी नागरिकों, युवाओं, किसानों से जल संरक्षण की अपील की और कहा कि अटल भूजल योजना उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां भूजल स्तर बहुत नीचे चली गई है या तेजी से नीचे जा रही है. उन्होंने कहा कि अटल भू-जल योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन सात राज्यों को होगा जहां भू-जल का स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बहुत फायदा मिलेगा. इन सात राज्यों के 78 जिलों में 8300 से ज्यादा गांवों में भू-जल की स्थिति बहुत खतरनाक है. हमें समझना होगा कि भू-जल इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नम्बर पर है. रिपोर्ट बताती है कि भारत अकेले इतना भू-जल इस्तेमाल करता है जितना कि अमरीका और हमसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन मिलकर करते हैं.

देश में पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर है और सरकार इस गंभीरता को बखूबी समझ रही है. ऐसा लगता है कि सरकार उन समस्याओं के स्थायी और ठोस समाधान के लिए गंभीर है और लगातार प्रयास कर रही है. ऐसे में जल समस्या के समाधान में जल शक्ति अभियान जैसे सरकारी योजनाओं से काफी लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं. ई-मेलः chandanchoudhary84@gmail.com)